



- अहमदाबाद को "2030 राष्ट्रमंडल खेलों" की मेजबानी का अधिकार औपचारिक रूप से प्रदान किया गया।
- भारत में पहली बार सिंटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण के लिए मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी—सरकार सात हजार दो सौ अस्सी करोड़ का निवेश करेगी।
- चुनाव आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने विशेष गहन पुनरीक्षण पर अंडमान निकोबार प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की।
- जहाजरानी सेवा निदेशालय ने कड़े निर्देश जारी करते हुए अतिरिक्त माल ढुलाई पर प्रतिबंध लगाया।



अहमदाबाद को वर्ष दो हजार तीस के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का अधिकार औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। ग्लासगो में आयोजित महासभा में चौहत्तर राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी, जिससे भारत को दूसरी बार इन खेलों की मेजबानी का अवसर मिला है। इससे पहले वर्ष दो हजार दस में नई दिल्ली ने राष्ट्रमंडल खेलों की सफल मेजबानी की थी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि खेलों के आयोजन का यह सम्मान देश के लिए गौरव का क्षण है और भारत को वर्ष दो हजार सैंतालीस तक खेल महाशक्ति बनाने के प्रयासों को गति देगा। अहमदाबाद जिसने पिछले एक दशक में अपने खेल ढांचे को व्यापक रूप से आधुनिक बनाया है, ओलंपिक मेजबानी की दौड़ में भी शामिल है। वर्ष दो हजार तीस के संस्करण में पंद्रह से सत्रह खेल शामिल किए जाएंगे और अंतिम खेल सूची अगले वर्ष तय होगी। इन खेलों का उद्देश्य खिलाड़ियों और समुदायों को एकजुट करना तथा राष्ट्रमंडल की खेल परंपरा के सौ वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाना है।



केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कल देश में सिंटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सात हजार दो सौ अस्सी करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। यह पहली बार है जब देश में छह हजार मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की एकीकृत उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और इनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन नवीकरणीय ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक्स एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह योजना देश में दुर्लभ धातु ऑक्साइड से धातु तैयार करने, धातु से मिश्रधातु बनाने और मिश्रधातु से तैयार मैग्नेट बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया को देश में विकसित करेगी।



दिल्ली की एक अदालत ने लाल किले विस्फोट मामले के सातवें आरोपी सोयब को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की दस दिन की हिरासत में भेज दिया है। उसे एनआईए ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। सोयब को कल पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे एनआईए की हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अदालत ने एक अन्य आरोपी आमिर राशिद अली की हिरासत भी सात दिनों के लिए बढ़ा दी है। एनआईए के अनुसार जांच में यह सामने आया है कि सोयब ने दस नवम्बर को हुए कार विस्फोट से पहले आतंकी उमर उन नबी को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की थी, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई थी और कई घायल हुए थे। एजेंसी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है, ताकि इस हमले की पूरी साजिश का खुलासा किया जा सके।



कृषि विभाग ने द्वीपसमूह में क्षेत्रीय केले की किस्मों के लिए टिशू कल्चर प्रोटोकॉल विकसित करने हेतु 4 अधिकारियों को प्रशिक्षण पर भेजा है। यह प्रशिक्षण 24 से 29 नवम्बर तक आई सी ए आर-राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में आयोजित किया जा रहा है। स्थानीय किसानों के लिए यह एक बड़ी पहल होगी, जिससे वे उन्नत वैज्ञानिक विधियों द्वारा अपनी फसल की उत्पादकता में वृद्धि कर सकेंगे। विभाग का उद्देश्य स्थानीय किस्मों को संरक्षित करते हुए बेहतर उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है।



भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त डॉ. विवेक जोशी द्वीपसमूह के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दौरान उन्होंने कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर के संबंध में द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। इस संशोधन का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना और मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और डुप्लिकेट मतदाताओं को हटाना है।

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल. कुमार ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 27 अक्टूबर, 2025 तक द्वीपसमूह में कुल 3,10,404 मतदाता पंजीकृत हैं, जिसमें 1,60,523 पुरुष, 1,49,877 महिलाएं और 4 थर्ड जेंडर शामिल हैं। इसके अलावा, लगभग 2,21,391 भरे हुए नामांकन पत्र एकत्र किए गए हैं। डॉ. जोशी ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रौद्योगिकी के लाभ का उपयोग करते हुए सुचारु रूप से चलाने पर संतोष व्यक्त किया और युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अधिकारियों को प्रेरित किया।



भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण –एसआईआर के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 4 नवम्बर से नामांकन पत्रों का वितरण और संकलन शुरू किया गया है। इस दौरान, कई बृथ स्तर अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में 100 प्रतिशत वितरण, संग्रह और डिजिटलीकरण का कार्य पूर्ण किया है। इन अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यशैली के लिए प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल. कुमार ने एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित सभी कर्मचारियों की सराहना की, जिन्होंने अपने क्षेत्र का कार्य समय पर पूरा किया। जो मतदाता अब तक नामांकन पत्र नहीं भर पाए हैं, उनसे 4 दिसम्बर से पहले प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है।



जहाजरानी सेवा निदेशालय ने निर्देश जारी करते हुए जेट्टी पर माल की ढुलाई से संबंधित अतिरिक्त सामान पर प्रतिबंध लगाया है। विभाग ने ढुलाई की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए, माल बुकिंग नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है।



इग्नू की टर्म एंड परीक्षा पहली दिसम्बर से आयोजित की जाएगी। सभी छात्रों से अपना प्रवेश पत्र समर्थ पोर्टल से डाउनलोड करने को कहा गया है। परीक्षा के लिए सभी आवश्यक जानकारी और निर्देश पोर्टल पर उपलब्ध हैं।



मौसम विभाग ने आज निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई है। इस दौरान हवा की गति पचास से साठ किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चलेगी। द्वीपसमूह के विभिन्न स्थानों पर 29 नवम्बर तक वर्षा हो सकती है। स्थानीय बंदरगाह पर खतरे का संकेत नम्बर-3 लगाया गया है।



समाचार पत्रों की सुर्खियां

द डेली टेलीग्राम्स और द्वीप समाचार ने भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी द्वारा द्वीपसमूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करने के समाचार को अपनी पहली हेडलाइन बनाते हुए सचित्र प्रकाशित किया है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा अगले महीने कैंसर से संबंधित दवाईयां उपलब्ध कराने के समाचार को द अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने अपने अखबार में जगह दी है। इंफो इंडिया और द इको ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय विधि दिवस के उपलक्ष्य में अंडमान विधि कॉलेज की ओर से रैली आयोजित करने के समाचार को प्रमुखता दी है।

